बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 13 ● नई दिल्ली ● शनिवार 18 अक्तूबर 2025 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

चोरी की घटना का पर्दाफाश,एक आरोपी गिरफ्तार,मोबाइल व नकदी बरामद

कुशीनगर। जनपद कुशीनगर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई का करते हुए 24 घंटे के भीतर चोरी की घटना का खुलासा कर दिया। थाना जटहां बाजार पुलिस ने मु0अ0सं0 158/2025 धारा 331(4)/305(A)/317(2) बीएनएस से संबंधित चोरी के मामले में अभियुक्त संजय पुत्र नगीना निषाद, निवासी हिरनही (बिन टोली), थाना जटहां बाजार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अभियुक्त के पास से चोरी के दो स्मार्टफोन (VIVO V23 व Samsung Ultra 23), 5100 नगद तथा चोरी करने में प्रयुक्त उपकरण बरामद किए हैं। थानाध्यक्ष आलोक कुमार के नेतृत्व में उ0नि0 विकास कौल व का0 विश्वजीत राय की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रारंभ कर दी है।

उच्चतम न्यायालय ने देश में 'डिजिटल अरेस्ट' की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताई, केंद्र का जवाब मांगा

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने हरियाणा के अंबाला में अदालत और जांच एजेंसियों के फर्जी आदेशों के आधार पर एक बुजुर्ग दंपति को 'डिजिटल अरेस्ट' कर उनसे 1.05 करोड़ रुपये की उगाही की घटना को शुक्रवार को गंभीरता से लिया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने देश भर में डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई और 73 वर्षीय महिला द्वारा भारत के प्रधान न्यायाधीश बी आर गवई को लिखे पत्र पर स्वतः संज्ञान लेते हुए दर्ज किए गए मामले में केंद्र और सीबीआई से जवाब मांगा। पीठ ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों सहित निर्दोष लोगों को डिजिटल अरेस्ट करने के लिए उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के आदेशों और न्यायाधीशों के हस्ताक्षरों की जालसाजी करना न्यायिक संस्थाओं में लोगों के विश्वास और आस्था पर कुठाराघात है। 'डिजिटल अरेस्ट' ऑनलाइन धोखाधड़ी है, जिसमें जालसाज खुद को फर्जी तरीके से किसी सरकारी एजेंसी या पुलिस का अधिकारी बताकर लोगों पर कानून

तोड़ने का आरोप लगाते हुए उन्हें धमकाते हैं और गलत तरह से धन वसूली की कोशिश करते हैं। शीर्ष अदालत ने कहा, ''न्यायाधीशों के जाली हस्ताक्षरों वाले न्यायिक आदेश तैयार करना, कानून के शासन के अलावा न्यायिक व्यवस्था में जनता के विश्वास की नींव पर कुठाराघात करता है।

इस तरह की कार्रवाई संस्था की गरिमा पर सीधा हमला है।'' पीठ ने कहा कि इस तरह के गंभीर आपराधिक कृत्य को धोखाधड़ी या साइबर अपराध के सामान्य या एकल अपराध के रूप में नहीं माना जा सकता। पीठ ने कहा, ''हम इस तथ्य का न्यायिक संज्ञान लेने के लिए भी इच्छुक हैं कि यह मामला एकमात्र मामला नहीं है।

मीडिया में कई बार ये खबरें आई हैं कि देश के विभिन्न हिस्सों में ऐसे अपराध हुए हैं। इसलिए, हमारा मानना है कि न्यायिक दस्तावेजों की जालसाजी, निर्दोष लोगों, खासकर वरिष्ठ नागरिकों से जबरन वसूली/लूट से जुड़े आपराधिक उपक्रम का पूरी तरह से पर्दाफाश करने के लिए केंद्र और राज्य पुलिस के बीच समन्वित प्रयासों और कार्रवाई की आवश्यकता है।'' पीठ ने अटॉर्नी जनरल से सहायता मांगी और हरियाणा सरकार तथा अंबाला साइबर अपराध विभाग को बुजुर्ग दंपति के मामले में अब तक की गई जांच पर एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। यह मामला शिकायतकर्ता महिला द्वारा अदालत के संज्ञान में लाया गया था, जिन्होंने आरोप लगाया था कि घोटालेबाजों ने 3 से 16 सितंबर के बीच दंपति की गिरफ्तारी और निगरानी की बात करने वाला स्टाम्प और मुहर लगा एक जाली अदालती आदेश पेश किया और कई बैंक लेनदेन के माध्यम से एक करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी की। महिला ने कहा कि उन्हें गिरफ्तार करने की धमकी देते हुए फर्जी तरीके से सीबीआई और ईडी अधिकारी बनकर कुछ लोगों ने कई ऑडियो और वीडियो कॉल के जरिए अदालती आदेश दिखाए।

शीर्ष अदालत को बताया गया कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के विभिन्न प्रावधानों के तहत अंबाला स्थित साइबर अपराध विभाग में दो प्राथमिकी दर्ज की गई हैं।

स्वीडिश सैन्य कंपनी के एजेंट थे राजीव गांधी, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे का गंभीर आरोप

नई दिल्ली ।

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर एक दस्तावेज साझा किया और दावा किया कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी स्वीडिश सैन्य कंपनी के एजेंट थे। निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि 1970 में हथियारों की खरीद में राजीव गांधी भी दलाली में शामिल थे। निशिकांत दुबे का राजीव गांधी पर यह आरोप ऐसे समय सामने आया है, जब कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने निशिकांत दुबे पर हमला बोला है। सुप्रिया श्रीनेत ने निशिकांत दुबे की पत्नी की संपत्ति में आए जबरदस्त उछाल पर सवाल खड़े किए। गुरुवार को कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और उनकी उनके चुनावी हलफनामे के खिलाफ लोकपाल से हुई शिकायत का हवाला दिया। शिकायत में दावा किया गया है कि निशिकांत दुबे की पत्नी की संपत्ति साल 2009 में 50 लाख रुपये थी, जो साल 2024 में बढ़कर 32 करोड़ रुपये हो गई। हालांकि भाजपा सांसद की संपत्ति में कोई खास परिवर्तन नहीं आया है। कांग्रेस नेता के अनुसार, लोकपाल ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को अपना जवाब दाखिल करने के लिए चार हफ्ते का समय दिया है। सुप्रिया श्रीनेत ने सवाल उठाया कि भाजपा सांसद की आय नहीं बढ़ी है, लेकिन उनकी कुल संपत्ति में इजाफा हुआ है। ऐसे में ये पैसा कहां से आया? निशिकांत दुबे के साल 2024 में दाखिल किए गए चुनावी हलफनामे के अनुसार, उनकी पत्नी के पास कुल 28.94 करोड़ रुपये की चल संपत्ति है। वहीं उनके पास 6.48 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति भी है। सुप्रिया श्रीनेत ने आरोप लगाया कि भाजपा सांसद के हलफनामे में बताया गया है कि उन पर 1.2 करोड़ रुपये का कर्ज है, लेकिन कथित कर्जदाता अभिषेक झा का दावा है कि उसने दुबे की पत्नी को कोई कर्ज नहीं दिया। कांग्रेस ने इसे लेकर भाजपा सांसद से स्पष्टीकरण मांगा है।

दिवाली से पहले दिल्ली-यूपी में मिलावटखोरों पर बड़ा प्रहार! करोड़ों की नकली मिठाई जब्त, सेहत से खिलवाड़ भारी पड़ेगा

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने बृहस्पतिवार-शुक्रवार को पश्चिमी दिल्ली के रघुबीर नगर इलाके में छापेमारी कर 2,000 से 2,500 किलोग्राम तक मिलावटी दूध से बनीं मिठाइयां जब्त कीं। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। यह कार्रवाई क्षेत्र में बड़े पैमाने पर मिलावटी खाद्य पदार्थों के उत्पादन की सूचना मिलने के बाद की गई। पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, ''भारी मात्रा में मिलावटी दूध से बनी मिठाइयों के डिब्बे बरामद किए गए। जब्त किए गए उत्पाद की आपूर्ति त्योहारों से पहले शहर की विभिन्न मिठाई की दुकानों में की जानी थी।'' अधिकारी ने बताया कि जब्त की गई मिठाइयों के नमूने प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजे गए हैं ताकि मिलावट की प्रकृति और सीमा का पता लगाया जा सके। उन्होंने कहा कि जिस परिसर में मिठाइयां बनाई जा रही थीं उसे सील कर दिया गया है और जिम्मेदार लोगों की तलाश जारी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने दिवाली और छठ पूजा से पहले खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू की है और राज्य भर में लगभग 4.76 करोड़ रुपये मूल्य के 3,394 क्विंटल से ज्यादा मिलावटी खाद्य उत्पाद जब्त किए हैं। यह कार्रवाई त्योहारी सीजन के दौरान जन स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे एक विशेष अभियान के तहत की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने दिवाली और छठ पूजा से पहले खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू की है और राज्य भर में लगभग 4.76 करोड़ रुपये मूल्य के 3,394 क्विंटल से अधिक मिलावटी खाद्य उत्पाद जब्त किए हैं। यह कार्रवाई त्योहारी सीजन के दौरान जन स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे एक विशेष अभियान के तहत की गई है। ÷दीपावली विशेष अभियान÷ नामक यह अभियान 8 अक्टूबर से शुरू हुआ और 17 अक्टूबर तक चलेगा। विभाग ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि इस दौरान अधिकारियों ने 5,464 निरीक्षण और 2,448 छापे मारे हैं और परीक्षण के लिए 3,369 खाद्य नमूने एकत्र किए हैं। खाद्य सुरक्षा आयुक्त रोशन जैकब ने कहा कि यह अभियान खाद्य पदार्थों में मिलावट पर अंकुश लगाने में बेहद प्रभावी रहा है। उन्होंने कहा, दिवाली और छठ के त्योहारी सीजन के दौरान जन स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।÷

आपको राष्ट्रपति संदर्भ पर हमारी सलाह का इंतजार करना होगा, तमिलनाडु सरकार से बोला शीर्ष कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तमिलनाडु सरकार से कहा कि वह राष्ट्रपति संदर्भ पर सलाह का इंतजार करे, उसके बाद ही अपनी उस याचिका पर आगे बढ़े, जिसमें राज्यपाल आर. एन. रवि के कदम को चुनौती दी गई है। राज्यपाल ने तमिलनाडु शारीरिक शिक्षा एवं खेल विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025 को मंजूरी देने की बजाय राष्ट्रपति के पास भेज दिया था। चीफ जस्टिस (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने कहा कि इस मामले की सुनवाई संविधान पीठ के फैसले के बाद होगी। बेंच ने कहा, आपको राष्ट्रपति संदर्भ के नतीजे का इंतजार करना होगा। मुश्किल से चार हफ्ते ही लगेंगे। यह फैसला 21 नवंबर से पहले आ जाएगा (क्योंकि तब तक जस्टिस गवई सेवानिवृत्त हो जाएंगे)। शीर्ष कोर्ट ने 11 सितंबर को उस राष्ट्रपति संदर्भ पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसमें यह सवाल उठाया गया था कि क्या सांविधानिक अदालतें राज्यपालों और राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए समयसीमा तय कर सकती हैं। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास नहीं भेज सकते, जब उन्हें मंत्रिपरिषद की सलाह और अनुशंसा मिल चुकी हो। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि वर्ष 2015 से 2025 तक देशभर के राज्यपालों की ओर से कुल 381 संदर्भ राष्ट्रपति के पास भेजे गए हैं। उन्होंने कहा, अगर ऐसे मामलों को न्यायिक समीक्षा के दायरे में लाया गया, तो माननीय न्यायालय को इन मुद्दों के लिए दो

स्थायी पीठें बनानी पड़ेंगी। राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि असल सवाल यह है कि क्या राज्यपाल हर विधेयक की हर धारा को जज की तरह जांच सकते हैं। तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में कहा है कि राज्यपाल द्वारा विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए भेजना स्पष्ट रूप से असांविधानिक, संविधान के अनुच्छेद 163(1) और 200 का उल्लंघन है और इसे शुरू से ही अवैध माना जाना चाहिए। याचिका के मुताबिक, यह विधेयक छह मई 2025 को मुख्यमंत्री की अनुशंसा के साथ राज्यपाल को मंजूरी के लिए भेजा गया था। लेकिन 14 जुलाई को राज्यपाल ने यह कहते हुए इसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया कि यह यूजीसी नियमावली 2018 की धारा 7.3 से टकरा सकती है। राज्य सरकार ने इस कदम को राज्यपाल की सांविधानिक शक्तियों से परे बताया है।

भीड़ में नहीं भटकेंगे यात्री, नई दिल्ली स्टेशन पर स्थायी होल्डिंग एरिया तैयार; आधुनिक इंतजाम

नई दिल्ली। त्योहारी सीजन में यात्रियों की भारी भीड़ देखते हुए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर स्थायी होल्डिंग एरिया तैयार किया गया है।

यात्रियों के प्लेटफॉर्म या सड़कों पर फंसने की स्थिति में यह एरिया राहत देगा। करीब सात हजार यात्रियों की क्षमता वाले इस क्षेत्र में बैठने, टिकटिंग, पानी और शौचालय की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इस एरिया में टिकट काउंटर भी शिफ्ट कर दिया गया है। रेलवे ने दीपावली और छठ पर्व की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए यह व्यवस्था शुरू की है।

टिकटिंग की अलग व्यवस्था

रेलवे ने पूरे क्षेत्र को तीन जोनों में बांटा है। पहले जोन में 1155, दूसरे में 2842 और तीसरे में 1284 यात्रियों की क्षमता है। यहां 25 टिकट काउंटर, 22 टिकट वेंडिंग मशीनें, 24 अनाउंसमेंट सिस्टम और 18 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। यात्री यहां से अनारक्षित विंडो से टिकट खरीद सकेंगे। महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग लाइन और बैठने की विशेष व्यवस्था की गई है।

यात्री सुविधा केंद्र में आधुनिक इंतजाम

होल्डिंग एरिया के यात्री सुविधा केंद्र में 150 से अधिक शौचालय, प्यूरीफाइड वॉटर की व्यवस्था और 200 यात्रियों के बैठने की क्षमता है। 18 एचवीएलएस पंखे लगाए गए हैं, 18 सीसीटीवी कैमरे और 5 लगेज स्कैनर और 5 डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर भी स्थापित किए गए हैं। स्टेशन परिसर में मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर एक के पास होल्डिंग एरिया बनाया गया है। यहां फुटओवर ब्रिज के पास से पैदल एरिया में जाना होगा।

एआई कैमरे रखेंगे नजर

रेलवे ने भीड़ प्रबंधन के लिए एआई आधारित कैमरों और सेंट्रल पब्लिक एड्रेस सिस्टम का प्रयोग शुरू किया है। एआई कैमरे भीड़ की रीयल टाइम निगरानी करेंगे और सीमा पार होते ही कंट्रोल रूम को अलर्ट भेजेंगे। 35 डिजिटल वॉकी-टॉकी डिवाइस स्टाफ को दिए गए हैं ताकि साइलेंट कोऑर्डिनेशन के जरिए भीड़ को संभाला जा सके। दिल्ली डिवीजन के सभी प्रमुख स्टेशनों पर मिनी-कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जो मुख्य कंट्रोल रूम को लगातार रीयल टाइम डेटा भेजेंगे।

समस्तीपुर और गोरखपुर के लिए श्री गंगानगर से 19 से विशेष ट्रेनें

उत्तर रेलवे ने दीपावली और छठ पर्व पर यूपी और बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए श्रीगंगानगर से समस्तीपुर और गोरखपुर के बीच साप्ताहिक स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है।

ट्रेन में वातानुकूलित, स्लीपर और सामान्य श्रेणी के डिब्बे शामिल होंगे। 04731 श्रीगंगानगर-समस्तीपुर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 19, 26 अक्टूबर और दो नवंबर को दोपहर 1:25 बजे श्रीगंगानगर से रवाना होगी। अगले दिन रात 11:00 बजे समस्तीपुर पहुंचेगी। 04732 समस्तीपुर-श्रीगंगानगर स्पेशल 21, 28 अक्टूबर और चार नवंबर को रात 1:00 बजे समस्तीपुर से रवाना होकर अगले दिन दोपहर 12:20 बजे श्रीगंगानगर पहुंचेगी। यह ट्रेन मार्ग में सादुलशहर, हनुमानगढ़, हिसार, रोहतक, दिल्ली जंक्शन, गाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली, सीतापुर, बस्ती, गोरखपुर, छपरा, हाजीपुर और मुजफ्फरपुर समेत कई प्रमुख स्टेशनों पर ठहरेगी। 04729 श्रीगंगानगर-गोरखपुर स्पेशल 23 और 30 अक्टूबर को (दो फेरों में) बृहस्पतिवार को चलेगी। यह दोपहर 1:25 बजे श्रीगंगानगर से रवाना होकर अगले दिन शाम 4:30 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। वापसी में 04730 गोरखपुर-श्रीगंगानगर स्पेशल 24 और 31 अक्टूबर को शुक्रवार को चलेगी, जो रात 7:30 बजे गोरखपुर से रवाना होकर तीसरे दिन सुबह 2:45 बजे श्रीगंगानगर पहुंचेगी।

रेलवे के कई आरक्षण केंद्र सायंकालीन पारी में रहेंगे बंद

उत्तर रेलवे ने दीपावली के अवसर पर दिल्ली में अपने यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) केंद्रों के कामकाज में आंशिक बदलाव किया है। 20 अक्टूबर को दीपावली के दिन कई आरक्षण केंद्रों में केवल सुबह की पारी में काम होगा, जबकि कुछ केंद्र पूरे दिन बंद रहेंगे। रेलवे के अनुसार आईआरसीएटी भवन, दिल्ली जंक्शन और हजरत निजामुद्दीन आरक्षण कार्यालयों में सायंकालीन पारी में सेवाएं शाम 6 बजे तक उपलब्ध रहेंगी।

सायंकालीन पारी में दोपहर 2 से रात 8 बजे तक सरोजिनी नगर, कीर्ति नगर, शकूरबस्ती, दिल्ली शाहदरा, गाजियाबाद, कड़कड़डूमा, ओखला, नोएडा, तुगलकाबाद, सब्जी मंडी, आदर्श नगर, लाजपत नगर, रोहिणी, एम्स और अंतरराष्ट्रीय टूरिस्ट ब्यूरो केंद्र बंद रहेंगे। इन केंद्रों पर सुबह की पारी सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक सामान्य रूप से कार्यरत रहेंगी। संसद भवन, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, रेलवे बोर्ड, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट स्थित आरक्षण केंद्र पूरे दिन बंद रहेंगे।

आज से 26 तक पार्सल सेवाएं बंद

उत्तर रेलवे ने रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए दिल्ली क्षेत्र में पार्सल यातायात पर अस्थायी रोक लगा दी है। नई दिल्ली, दिल्ली जंक्शन और आनंद विहार टर्मिनल से चलने वाली ट्रेनों में 17 से 26 अक्तूबर तक सभी प्रकार के पार्सल लेन-देन पर रोक रहेगी। साथ ही, रेलवे के माध्यम से सीधी पार्सल बुकिंग पर भी 15 से 26 अक्तूबर तक रोक रहेगी। इस अवधि में पार्सल गोदामों और प्लेटफॉर्मों को पार्सल पैकिंग या लेन-देन से मुक्त रखा जाएगा। हालांकि, यात्री डिब्बों में व्यक्तिगत सामान की अनुमति होगी। इसके अलावा सभी आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद पंजीकृत समाचार पत्रों और पत्रिकाओं की बुकिंग की अनुमति दी जाएगी। यह अस्थायी प्रतिबंध न केवल दिल्ली क्षेत्र के प्रमुख स्टेशनों पर लागू रहेगा बल्कि उन ट्रेनों पर भी लागू होगा जो दिल्ली क्षेत्र से होकर गुजरती हैं और यहां लोडिंग या अनलोडिंग का स्टॉपेज रखती हैं।

वक्फ के दांव-पेंच

बहुप्रतीक्षित सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर मिश्रित प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। विभिन्न वर्ग, विशेषकर मुसलमान सतर्क दिखाई दिए और अपनी निराशा को एक तरह से आशा के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। यह कहना मुश्किल है कि उन्होंने कम उम्मीद की थी या ज्यादा लेकिन शायद उन्हें इस बात में सांत्वना मिलती है कि यह एक अंतरिम निर्णय है और इसलिए आशा अभी जीवित है, जैसा कि खालिद राशिद फ़रंगी महली ने एक साक्षात्कार में कहा। फ़रंगी, महल परिवार के वंशज और एक धर्मगुरु, मौलाना खालिद राशिद फ़रंगी महली इस्लामिक विद्वान और समाज सुधारक हैं। एक प्रतिष्ठित वंश के सदस्य, जिसने 1,000 वर्षों से अधिक समय से इस्लामी विद्वानों को जन्म दिया है, मौलाना खालिद राशिद लखनऊ ईदगाह के इमाम के रूप में कार्यरत हैं। वे अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सबसे युवा कार्यकारिणी सदस्य भी हैं और सभी धर्मों के लोगों के बीच भाईचारे और मित्रता को बढ़ावा देते हैं। शायद इसी कारण, जब हाल ही में वक्फ कानून के विरोध में प्रदर्शन की बात आई, तो वे आक्रामक की बजाय शांतिपूर्ण तरीके के पक्षधर थे। मौलाना महली ने कहा ÷बोर्ड के अधिकांश सदस्य इस विचार में थे कि बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए जाने चाहिए, जबकि कुछ जैसे मैं यह मानते थे कि प्रदर्शन सीमित होने चाहिए लेकिन बोर्ड ने निर्णय संबंधित राज्यों पर छोड़ दिया। अपने राज्य उत्तर प्रदेश में हमने विरोध-प्रदर्शन किए लेकिन सड़कों पर नहीं उतरे। हमने मस्जिदों में फतवे और भाषण जारी किए, काले बैंड बांधे और बत्ती गुल, 'लाइट्स ऑफ' जैसे प्रदर्शन किए। पर्सनल लॉ बोर्ड ने समुदाय से वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिए विशेष दुआएं और नमाज़ें करने का अनुरोध किया। सच यह है कि मुसलमान दो मोर्चों पर हताश महसूस कर रहे हैं पहला, भाजपा सरकार द्वारा वक्फ पर केन्द्रित नए कानून के जरिए उन पर ध्यान देना और दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राहत न देना। समुदाय की दृष्टि में राहत की परिभाषा है पूरे अधिनियम को रद्द करना। जब सरकार ने अनुपालन नहीं किया तो उन्होंने न्यायिक हस्तक्षेप मांगा, लेकिन यहां भी, जैसा कि कई लोग देखते हैं, आंशिक न्याय÷ ही मिला। फिर भी वे हतोत्साहित नहीं हैं। अधिकांश का मत है हम अल्लाह पर विश्वास करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला शायद वैसा नहीं है जैसा हम चाहते थे लेकिन हम इसे हार नहीं मानते। हम अंतिम फैसले का इंतजार करेंगे। फिलहाल, हमें 10 प्रतिशत राहत मिली है लेकिन यह अंतरिम है, अंतिम आदेश नहीं। समूह की सहमति है उम्मीद पर दुनिया कायम है और उम्मीद ज़िंदा है। आज 10 प्रतिशत मिली है, इंशाअल्लाह बाकी 90 प्रतिशत भी मिलेगी। हालांकि, मुसलमान इस बात को देखते हैं कि इस अधिनियम के लागू होने से संभावित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। साथ ही, वे यह भी नहीं नकारते कि वक्फ बोर्डों के कामकाज में सुधार की गुंजाइश थी। फ़रंगी महली के शब्दों में ÷समाधान यह नहीं है कि वक्फ की आत्मा को बदल दिया जाए या नष्ट कर दिया जाए। आत्मा तो खत्म नहीं हो सकती, चीजें ठीक होनी चाहिए लेकिन जो सदियों से चली आ रही हैं, उनका अंत नहीं किया जा सकता।÷ यानी, दशकों से चली आ रही व्यवस्था में आवश्यक और वांछित बदलाव किए जा सकते हैं, न कि पूरी प्रणाली का खात्मा किया जाए। उन्होंने यह भी माना कि वक्फ बोर्डों में कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार मौजूद था लेकिन इन पहलुओं से निपटने के लिए कानून में पर्याप्त प्रावधान मौजूद थे। समुदाय की अधिकांश राय को व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा समुदाय की भावना यह है कि यह मुसलमानों का आंतरिक, धार्मिक और इस्लामी मामला है और इससे छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। 1995 के अधिनियम में डिफॉल्टर्स के खिलाफ कार्रवाई के पर्याप्त प्रावधान मौजूद थे। इसलिए ध्यान यह होना चाहिए था कि इन प्रावधानों को मजबूत और प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, न कि पुराने कानून को रद्द करके नया अधिनियम लाया जाए। वक्फ संपत्तियों को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा नए कानून लाने के पीछे किसी छिपे हुए उद्देश्य को लेकर माहली सतर्क रहे। उन्होंने कहा- इसका सबसे अच्छा जवाब भाजपा सरकार ही दे सकती है। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि जब कोई नया कानून लाया जा रहा हो तो संबंधित समुदाय के सदस्यों से परामर्श किया जाना चाहिए और उन्हें विश्वास में लिया जाना चाहिए। उनका सुझाव लेने के बजाय समुदाय से अधिनियम बनने के बाद ही राय ली गई। हर समुदाय के लिए ट्रस्ट बने हैं लेकिन किसी में हस्तक्षेप नहीं किया जाता, सिवाय मुसलमान समुदाय से संबंधित मामलों के। यही वजह है कि नाराजगी और शंका उत्पन्न हुई कि वक्फ के तहत संपत्तियां और मुसलमानों के धार्मिक अधिकार अब सुरक्षित नहीं हैं। हमें लगता है कि हम अपनी मस्जिदों, मदरसों और कब्रिस्तानों पर नियंत्रण खो देंगे। सरकार के इस तरह के कदमों से ऐसा लगता है कि नया अधिनियम समुदाय को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने यह भी जोड़ा कि यह गलत धारणा जानबूझकर पैदा की जा रही है कि यदि कोई मुसलमान किसी संपत्ति पर हाथ डालता है तो वह वक्फ़ मानी जाएगी। वास्तविकता इससे अलग है। वक्फ की पवित्रता पर ज़ोर देते हुए माहली ने कहा कि वक्फ़ संपत्तियों के दुरुपयोग का कोई भी प्रयास इस्लामी नहीं है और मुसलमानों के लिए यह पर्याप्त रोकथाम है कि वे इस्लाम के सिद्धांतों के खिलाफ कुछ न करें। उन्होंने कहा कि वक्फ संपत्तियों का अधिकांश हिस्सा कब्रिस्तानों और दरगाहों के रूप में है। ये आय उत्पन्न करने वाली संपत्तियां नहीं हैं, इसके विपरीत इनका रखरखाव और संचालन करने में खर्चा आता है। माहली ने यह भी खंडन किया कि वक्फ संपत्तियां विशाल भूमि का भंडार हैं, जो सेना और रेलवे के बाद तीसरी सबसे बड़ी संपत्ति मानी जाती हैं। उन्होंने सरकार से यह भी मांग की कि अन्य धार्मिक संस्थानों की संपत्तियों की संख्या और जानकारी भी सार्वजनिक की जाए। इन आंकड़ों को पेश करके भ्रम पैदा करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अधिकांश संपत्तियां आय उत्पन्न करने वाली नहीं हैं। क्या मृतकों से कोई आय उत्पन्न की जा सकती है? उन्होंने दोहराया कि अधिकांश वक्फ़ संपत्तियां कब्रिस्तान या मस्जिदें हैं।

सम्पादकीय...

पाकिस्तान-अफगानिस्तान युद्ध

बीते दिनों भारतीय उप-महाद्वीप में बेहद दिलचस्प घटनाक्रम सामने आया। जब तालिबान शासित अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्ताकी भारत के महत्वपूर्ण दौरे पर रहे, तब पाकिस्तान-अफगानिस्तान की डूरंड सीमा पर तालिबानी लड़ाके और पाकिस्तानी फौज एक-दूसरे पर गोला-बारूद बरसा रहे थे। यह तनाव 11 अक्तूबर की रात तब बढ़ गया, जब पाकिस्तानी हवाई हमले के जवाब में अफगान बलों ने सीमा पार करके कई सैन्य चौकियां कब्जा लीं। दोनों ओर कई सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं। यह सुनने में कितना अजीबो-गरीब है कि वैश्विक आतंकवाद का घोषित गढ़ पाकिस्तान, इस्लाम के अतिवादी स्वरूप तालिबान पर आरोप लगा रहा है कि वह आतंकियों को पनाह देता है जो सीमा पार करके उस पर हमले करते हैं। क्या यह सच नहीं कि भारत दशकों से पाकिस्तान की ओर से इसी तरह के संकट से दो-चार है? आखिर पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच तनाव की असली वजह क्या है? क्यों भारत तालिबान से नजदीकी बढ़ा रहा है? सामान्यतः एक इस्लामी देश होने और उसमें भी सुन्नी संप्रदाय की प्रधानता के कारण पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच सौहार्दपूर्ण भाईचारे और अच्छे पड़ोसी जैसे संबंध होना स्वाभाविक थे। जब अगस्त 2021 में अमरीका ने दो दशक के कब्जे पश्चात एक समझौते के तहत अफगानिस्तान की सत्ता तालिबान को फिर से सौंपी, तब पाकिस्तान को लगा कि यह उसकी भारत-विरोधी रणनीति को धार देगा। लेकिन यह हसीन ख्वाब ज्यादा लंबा नहीं चला। अफगानिस्तान वर्ष 1893 में ब्रिटिश हुकूमत के दौरान खींची गई डूरंड रेखा को आज भी मान्यता नहीं देता है जो इन दोनों देशों के बीच आपसी विवाद का एक बड़ा कारण भी है। परंतु वर्तमान टकराव की वजह मुत्ताकी का हालिया भारत दौरा और संयुक्त वक्तव्य है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद भारत-अफगानिस्तान ने 10 अक्तूबर को साझा बयान जारी किया था। इसमें जम्मू-कश्मीर को भारत का अभिन्न और संप्रभु हिस्सा बताते हुए 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए पाकिस्तान-प्रायोजित आतंकवादी हमले की निंदा की गई थी। इस दौरान मुत्ताकी ने भारत को यकीन दिलाया कि अफगानिस्तान 'आतंकवाद का सख्त विरोधी' है और वह किसी को भी अफगान धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने के लिए नहीं करने देगा। वहीं भारत ने काबुल में भारतीय दूतावास खोलने का ऐलान किया है। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता के प्रति सम्मान पर भी जोर दिया। यह सब पाकिस्तान को चुभना स्वाभाविक ही था और संभवतः इसी कारण उसने बौखलाकर अफगानिस्तान पर हवाई हमला कर दिया। वास्तव में,संकट पाकिस्तान के डी.एन.ए. में छिपा है। अपने पिछले लेखों में मैंने स्पष्ट किया था कि पाकिस्तान न तो सचमुच कोई इस्लामी देश है और न ही उसका भारतीय उपमहाद्वीप के मुसलमानों से कोई सरोकार है। पश्चिमी शक्तियों ने उसे अपनी राजनीतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया था और वह आज भी उसी भूमिका में है। उनके लिए इस्लाम सिर्फ एक बहाना है और मुस्लिम महज औजार। मुसलमान आमतौर पर फिलिस्तीन-ईरान से सहानुभूति रखते हैं। लेकिन बीते दिनों पाकिस्तान प्रत्यक्ष-परोक्ष रूप से उनके खिलाफ इस्राईल-अमरीका का सहयोग करता रहा। पाकिस्तान द्वारा इसराईल स्वीकृत 'गाजा योजना' का समर्थन इसका एक और हालिया प्रमाण है। अब इसके खिलाफ पाकिस्तान में 'तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान' जैसे जिहादी संगठन हिंसक प्रदर्शन पर उतर आए हैं। आखिर भारत ने तालिबान से दोस्ती का हाथ क्यों बढ़ाया? यह अकाट्य सत्य है कि भारत दुनिया के सबसे तनावग्रस्त और अस्थिर क्षेत्र में स्थित है, जहां वह ऐसे पड़ोसियों (पाकिस्तान, चीन और बंगलादेश) से घिरा है जो मजहबी और साम्राज्यवादी कारणों से भारत को मिटाना, बर्बाद और कमजोर करना चाहते हैं। ऐसा भी नहीं है कि भारत ने अफगानिस्तान से अभी संबंध सुधारने की पहल की हो। वर्ष 2020-2021 के दौरान भारत ने अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण और विकास कार्यों पर लगभग 3 अरब डालर का निवेश किया था, जिसमें सड़क, बिजली, पानी, बांध के साथ अफगान संसद भवन के निर्माण सहित 400 परियोजनाएं शामिल हैं। इस पृष्ठभूमि में एक प्रसिद्ध मुहावरा है-'दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है'। सफल 'आप्रेशन सिंदूर' के बाद बदलते वैश्विक परिप्रेक्ष्य, जिसमें पाकिस्तान से डोनाल्ड ट्रम्प के नेतृत्व में अमरीका निकटता बढ़ा रहा है, उस स्थिति में भारत अपनी क्षेत्रीय अखंडता और सुरक्षा हेतु राष्ट्रहित में सामरिक रणनीति-कूटनीति में संतुलित और आवश्यक परिवर्तन कर रहा है। इसके साथ भारत-ईरानी चाबहार बंदरगाह का विकास करने के साथ अफगानिस्तान के जरिए भी मध्य-एशिया तक सीधी पहुंच भी बनाना चाहता है। यह दिलचस्प है कि दिसंबर 1999 के कंधार अपहृत विमान प्रकरण में भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल उस समय मुख्य वार्ताकारों में से एक थे और तब मुत्ताकी तालिबान प्रशासनिक मामलों को देखते थे। 26 साल बाद वही दोनों व्यक्ति एक बार फिर असामान्य भू-राजनीतिक घटनाक्रम के केंद्र में हैं। क्या पाकिस्तान वाकई अफगानिस्तान को झुकाने की ताकत रखता है? 'काफिर-कुफ्र' अवधारणा से प्रेरित मजहबी चिंतन से अलग अगर पिछले 5 दशकों का इतिहास देखें तो कोई भी शक्तिशाली देश अफगानिस्तान को स्वाभिमान की लड़ाई में निर्णायक रूप से हरा नहीं पाया है। शीतयुद्ध के दौर में अफगानिस्तान पर सोवियत संघ ने 1979 में कब्जा कर लिया था। तब अमरीका ने पाकिस्तान और सऊदी अरब की मदद से अफगान विद्रोहियों का मुजाहिदीनों का समूह तैयार किया। वर्तमान समय में अमरीका और चीन, दोनों अपने 'दुमछल्ले' पाकिस्तान की मदद से अफगानिस्तान के विशाल और अनछुए खनिजों तक पहुंचना चाहते हैं। इसलिए पाकिस्तान अपने आकाओं के लिए अफगानिस्तान को कठपुतली बनाना चाहता है। अब जिस अफगानिस्तान को सोवियत रूस और अमरीका नहीं दबा सके, क्या उसे पाकिस्तान झुका सकता है?

दिवाली ग्रीन पटाखों वाली

हर वर्ष दिवाली पर दिल्ली और एनसीआर के शहरों में धुएं का साया चढ़ जाता है। महानगर विषाक्त गैसों का चैम्बर बन जाता है। लोगों को सांस लेने में भी परेशानी होती है। लाख कोशिशों के बावजूद प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा। दिल्ली में वायु गुणवत्ता अभी से ही प्रभावित होने लगी है। दिल्ली का एक्यूआई 300 के पार पहुंच गया है जो कि अति खराब श्रेणी में है। दीपावली का त्यौहार रोशनियों का त्यौहार है। शहरों से बाजार गुलजार हैं। भारत में बिना पटाखों के दीपावली के त्यौहार की कल्पना नहीं की जा सकती। पटाखों पर प्रतिबंध लोगों की जनभावनाओं के अनुकूल नहीं रहा। सच्चाई यह है कि पाबंदियां भी पटाखों को नहीं रोक पाईं। इससे पटाखों की तस्करी बढ़ जाती है और नतीजा वही होता है कि हर साल दिवाली के बाद दिल्ली का दम घुटता है। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपने पुराने आदेश में ढील देने का आग्रह करते हुए जनभावनाओं के दृष्टिगत ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति मांगी थी, जिसे शीर्ष अदालत ने स्वीकार कर लिया है। सर्वोच्च अदालत ने 18 से 21 अक्तूबर तक सुबह 6 से 7 बजे तक और रात 8 से 10 बजे तक ग्रीन पटाखे चलाने के लिए समय तय किया है। सर्वोच्च अदालत ने संतुलित दृष्टिकोण अपनाया है। हरियाणा के 22 जिलों में से 14 जिले एनसीआर में आते हैं। उत्तर प्रदेश के शहर भी एनसीआर में हैं। जब पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया था तो कोरोना के समय को छोड़कर एयर क्वालिटी में बहुत अंतर नहीं था। कोरोना काल में तो हिमालय की पर्वतीय श्रृंखला भी कुछ शहरों में साफ नजर आने लगी थीं। अर्जुन गोपाल मामले में फैसले के बाद ग्रीन पटाखों की अवधारणा पेश की गई थी। 6 वर्षों में ग्रीन पटाखों ने उत्सर्जन को काफी कम कर दिया है। ग्रीन पटाखे ऐसे पटाखे होते हैं जो पारंपरिक पटाखों के मुकाबले पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाते हैं। इनमें एल्युमिनियम, पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर जैसे हानिकारक केमिकल्स या तो बहुत कम मात्रा में होते हैं या बिल्कुल नहीं होते। ग्रीन पटाखों में बेरियम पदार्थ नहीं होता है, जिसका इस्तेमाल पटाखों में ग्रीन कलर डालने के लिए किया जाता है। पारंपरिक पटाखे काले पाउडर, क्लोरेट्स और परक्लोरेट्स से बने होते हैं। ग्रीन पटाखों की खोज सीएसआईआर-नीरी ने की थी। ग्रीन पटाखों की पहचान सीएसआईआर-नीरी के हरे लोगो और पैकेट पर एन्क्रिप्टेड क्यूआर कोड से की जा सकती है। जहां सामान्य पटाखे 160 डेसिबल तक शोर करते हैं, वहीं ग्रीन पटाखों की आवाज 110 से 125 डेसिबल तक होती है। वर्ष के इस समय में, मौसम, उत्सव की प्रथाएं और क्षेत्रीय कृषि मिलकर ऐसी परिस्थितियां पैदा करते हैं जिसमें दिल्ली के आसपास वायु प्रदूषण स्वस्थ वायु के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक से 300 गुना अधिक हो जाता है। मानसून का मौसम खत्म हो गया है। इसका मतलब है कि प्रदूषण अब नहीं बढ़ेगा और तापमान में गिरावट के साथ प्रदूषक वायुमंडल में नीचे ही रह जाएंगे। दिवाली मनाने का मतलब है अनियंत्रित पटाखे जलाना, जो हवा में भारी मात्रा में जहरीले रसायन छोड़ते हैं। फसल कटाई के बाद दिल्ली और आसपास के शहरों से सटे हजारों एकड़ कृषि भूमि पर पराली जलाने का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में पिछले एक हफ्ते से पराली जलाने की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं, फिर भी पॉजिटिव सिग्नल यह है कि इस बार 6 राज्यों में? पिछले 30 दिनों में सिर्फ 552 पराली जलाने की घटनाएं दर्ज हुई हैं, जो 2020 से सबसे कम हैं। अब सवाल यह है कि क्या दिल्ली के लोगों को दिवाली के बाद स्वच्छ हवा मिल पाएगी। इसको लेकर पर्यावरण अनुसंधानकर्ताओं की राय अलग-अलग है। अनुसंधानकर्ता बताते हैं कि ग्रीन पटाखे भी बड़ी मात्रा में अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स रिलीज करते हैं जो इंसान के फेफड़ों में काफी अन्दर तक जा सकते हैं। ग्रीन पटाखों पर भी सवाल उठ रहे हैं। वहीं पिछले कुछ सालों से पटाखों पर प्रतिबंध को लेकर एक दूसरी बहस भी छिड़ चुकी है, इसका राजनीतिकरण हो गया है। कुछ नेताओं ने पटाखों पर लगाए प्रतिबंध को हिन्दू धर्म से जोड़ दिया है। दिल्ली में सर्दियों में वायु प्रदूषण अदृश्य नहीं रहता। जो अदृश्य रहता है वह है स्वास्थ्य पर पड़ने वाला प्रभाव। देश में हर साल 5 साल से कम उम्र के एक लाख बच्चे वायु प्रदूषण से होने वाली मौत का शिकार हो जाते हैं। लाखों लोग बीमारियों का शिकार होते हैं। इसके बावजूद समृद्धि की देवी लक्ष्मी का उत्सव मनाना एक गहरी विडम्बना है जिसका समाधान भारत को करना होगा। समृद्धि और स्वच्छ वायु के बीच टकराव नहीं होना चाहिए। बेहतर यही होगा कि लोग दिवाली के अंधकारमय पक्ष को समझें। दीप जलाएं प्रदूषण नहीं।

दीपावली और अर्थतंत्र

दिवाली का त्यौहार जैसे-जैसे करीब आ रहा है, पूरे देश के बाजारों में रौनक भी बढ़ती जा रही है। सजे-धजे बाजारों में लोगों की भीड़, खरीदारी का उत्साह और स्वदेशी उत्पादों की चमक इस साल की दिवाली को खास बना रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा 100 प्रतिशत टैरिफ लगाए जाने का भी कोई प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा। इस बार दिवाली पर बिक्री 4.75 लाख करोड़ रुपये के ऐतिहासिक आंकड़े को पार करने जा रही है, जो पिछले एक दशक में सबसे मजबूत त्यौहारी सीजन माना जा रहा है। भारत त्यौहारों का देश है और इन्हीं में से सबसे बड़ा पर्व है दीपावली। यह केवल धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। दीपावली को ÷भारत की सबसे बड़ी आर्थिक गतिविधि का मौसम भी कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान उपभोग, निवेश और व्यापार सभी अपने चरम पर पहुंचते हैं। जीएसटी दरों में की गई कमी और 'स्वदेशी' और 'वोकल फॉर लोकल' अभियान ने व्यापारी समुदाय के लिए बड़ा बदलाव लाया है। 'यह दिवाली केवल घरों को नहीं, बल्कि देश के लाखों व्यापारियों, निर्माताओं, कारीगरों और सेवा क्षेत्र से जुड़े लोगों के जीवन को भी रोशन करेगी।' उपभोक्ताओं का उत्साह देखते ही बन रहा है, हर वर्ग के लोग अपनी क्षमता के अनुसार खरीदारी कर रहे हैं। यह त्यौहार भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था की असली ताकत को उजागर कर रहा है, जहां करोड़ों परिवार छोटे-बड़े स्तर पर खर्च कर रहे हैं, जिससे हर व्यापारी वर्ग को लाभ मिल रहा है। जीएसटी की दरों में कटौती का पूरा असर दिखे उससे पहले सितंबर में खुदरा महंगाई दर में बड़ी कमी आई है। सितंबर में खुदरा महंगाई दर गिरकर आठ साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। सरकार की ओर से सोमवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक सितंबर में खुदरा महंगाई दर 1.54 फीसदी पर आ गई। इससे पहले जून 2017 में महंगाई दर इस स्तर पर थी। खाने-पीने की वस्तुओं की कीमतों में गिरावट की वजह से खुदरा महंगाई दर कम हुई है। इससे पहले अगस्त में खुदरा महंगाई 2.07 फीसदी रही थी। गौरतलब है कि महंगाई के आकलन करीब 50 फीसदी हिस्सा खाने पीने की चीजों का होता है। सितंबर के महीने में खाने पीने की चीजों की महंगाई महीने दर महीने के आधार पर माइनस 0.64 से घट कर माइनस 2.28 फीसदी हो गई। सितंबर महीने में ग्रामीण महंगाई दर 1.69 से घट कर 1.07 फीसदी और शहरी महंगाई 2.47 से घटकर 2.04 फीसदी पर आ गई है। भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी संकेतक बेहतर भविष्य की ओर इशारा कर रहे हैं। अन्तर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 6.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.9 फीसदी कर दिया है, जो देश की आर्थिक मजबूती का ही प्रमाण है। इसमें यह बदलाव मुख्य रूप से चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में मिली मजबूत आर्थिक वृद्धि और घरेलू मांग में आयी तेजी के कारण किया है। फिच के 'ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक सितंबर' रिपोर्ट में कहा गया है कि जनवरी-मार्च की तिमाही में 7.4 प्रतिशत की वृद्धि दर के मुकाबले अप्रैल-जून में विकास दर बढ़कर 7.8 फीसदी हो गयी, जो उसके जून में लगाये गये 6.7 प्रतिशत के अनुमान से कहीं अधिक है। भारतीय अर्थव्यवस्था में गति बनी हुई है, पीएमआई सर्वे और औद्योगिक उत्पादन इसकी ओर इशारा करते हैं। गौरतलब है कि व्यापारिक गतिविधियों का सूचक समग्र पीएमआई सूचकांक अगस्त में 17 वर्ष के शिखर पर पहुंच गया, जबकि औद्योगिक उत्पादन चार महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गया। जबकि ट्रंप द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था को मृत बताये जाने के बाद मजबूत अर्थव्यवस्था और विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन का हवाला देते हुए स्टैंडर्ड एंड पूअर्स ने 18 साल बाद भारत की रेटिंग बढ़ायी है। उल्लेखनीय है कि आईएमएफ, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक आदि ने भी अपनी रिपोर्टों में भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती के बने रहने को रेखांकित किया है। दिवाली को पारंपरिक रूप से सोना-चांदी खरीदने का शुभ अवसर माना जाता है। ऐसे में त्यौहार से पहले कीमतों में यह अप्रत्याशित वृद्धि ग्राहकों के लिए चिंता का विषय बन गई है। बाजार विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले दिनों में भी यदि वैश्विक परिस्थितियां ऐसी ही बनी रहीं तो चांदी और सोने के दामों में और बढ़ोतरी संभव है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तावित टैरिफ (शुल्क) नीतियों और अमेरिकी फेडरल बैंक द्वारा ब्याज दरों में की गई कटौती के कारण वैश्विक बाजार में निवेशक सुरक्षित निवेश के विकल्पों की ओर रुख कर रहे हैं।इसका सीधा असर चांदी और सोने की कीमतों पर पड़ा है। चांदी का बड़े पैमाने पर औद्योगिक इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल और औषधीय उपकरणों में इसकी खपत बढ़ने से मांग में तीव्र वृद्धि हुई है। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, चांदी की आपूर्ति में असंतुलन के कारण इसका स्टॉक घट गया है। इससे चांदी खरीदने के लिए ग्राहकों को 8 दिन पहले ऑर्डर देना पड़ रहा है। आर्थिक अनिश्चितता के इस दौर में निवेशक सुरक्षित और स्थिर माने-जाने वाले परिसंपत्तियों जैसे कि सोना और चांदी की ओर रुख कर रहे हैं। इसके चलते मांग में लगातार इजाफा हो रहा है। त्योहारी सीजन में सोने और चांदी की कीमतों ने अभी तक के सभी रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। एक बार फिर सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है।

सेहत से खिलवाड़ करते मिलावटखोर

मिलावट के इस दौर में असली-नकली में भेद करना बेहद मुश्किल जान पड़ता है फिर चाहे वे मानवीय संबंध हों या फिर दैनिक उपभोग में प्रयुक्त होने वाले खाद्य पदार्थ। सहायक धंधे के तौर पर आरम्भ हुई श्वेत क्रांति तक मुनाफाखोर की बदनीयती से काले धंधे में तबदील हो चुकी है। विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, देश के 89.2 प्रतिशत दुग्ध उत्पादों में किसी न किसी प्रकार की मिलावट पाई गई। राष्ट्रीय स्तर पर दुग्ध उत्पादन का आकलन करें तो देश में कुल 14 करोड़ लीटर दूध उत्पादित होता है, जबकि दैनिक खपत लगभग 65 करोड़ लीटर है। मांग व आपूर्ति में स्थित यह भारी अंतर कैसे पाटा जाता होगा, इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। त्यौहारों के दौरान मिठाइयों की बढ़ती मांग के दृष्टिगत पर्याप्त दूध कहां से आता है, यह भी किसी बड़े रहस्य से कम नहीं। जाहिर तौर पर नियमित आपूर्ति की इस भरपाई में एक बड़ा अंश वास्तव में कृत्रिम दूध का है, जिसे नकली दूध कंपनियों द्वारा विविध प्रकार के रसायनों की सहायता से तैयार किया जाता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण उत्पादित 68.7 प्रतिशत दूध के मानकों पर खरे न उतर पाने की बात पूर्व में ही बता चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के तहत भारत में प्रतिदिन बिकने वाले 64 करोड़ लीटर दूध में से 50 करोड़ लीटर दूध नकली या मिलावटी होता है। भारत के 70 प्रतिशत से अधिक दुग्ध उत्पाद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं उतरते। समृद्ध प्रांतों की श्रेणी में शुमार होने वाला पंजाब प्रांत भी इस विषय में अपवाद नहीं कहा जा सकता। राज्य खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफ.डी.ए.) की एक रिपोर्ट बताती है कि शुद्धता जांचने हेतु लिए गए दूध के नमूनों में अधिकांश न केवल गुणवत्ता-परीक्षण में असफल पाए गए बल्कि 41 प्रतिशत में स्वास्थ्य के लिहाज से घातक तत्व भी मौजूद रहे। बीते दिनों दूध व डेयरी उत्पादों में मिलावट के विरुद्ध की गई एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार की ओर से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने जवाब दायर करते हुए एक स्टेटस रिपोर्ट पेश की। सरकार की ओर से प्रदत्त जानकारी के अनुसार 2 जनवरी, 2019 से लेकर 31 दिसम्बर, 2024 तक राज्य में कुल 2,191 मामलों का निपटारा किया गया। इनमें लगभग 95 प्रतिशत मामलों में दंड लगाया गया। जुर्माने के रूप में वसूल की गई कुल राशि 3,04,75,720 आंकी गई। आंकड़े अमृतसर, गुरदासपुर, संगरूर तथा फतेहगढ़ साहिब जैसे जिलों में सर्वाधिक मामले दर्ज होने का खुलासा करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, मिलावट का यह क्रम न सिर्फ दूध उत्पादों तक ही सीमित रहा अपितु पनीर, दही, खोया, मक्खन, मिठाई, देसी घी आदि से लेकर आइसक्रीम, नमकीन, हल्दी एवं मिर्च पाऊडर, गुलाब शरबत, खाद्य तेलों तक में मिलावट देखने को मिली। पांच वर्षों में दर्ज 2,191 मामले स्वतः ही हालात की गंभीरता दर्शाते हैं। ऐसी अवस्था में व्यवस्थात्मक प्रबंधन पर सवालिया निशान उठना भी स्वाभाविक है। दोषियों की धर-पकड़ व भारी-भरकम जुर्माने के बावजूद यह धंधा क्यों और कैसे फल-फूल रहा है? या तो मुनाफाखोरों में कानून के प्रति भय ही नहीं अथवा तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार उन्हें मनमर्जी करने की इजाजत दे रहा है। दूध-दही बहाने वाले भारतवर्ष के इतिहास में एक ऐसा भी समय रहा, जब लगभग हर घर में ही पशुधन हुआ करता था। दूध से मुनाफा कमाना तत्कालीन समाज की दृष्टि में हेय था लेकिन आज समय पूर्णतः परिवर्तित हो चुका है। अब इस कारोबार में न केवल जमकर मुनाफाखोरी होती है बल्कि मिलावट की आशंका भी बराबर बनी रहती है। खासकर त्यौहार के दिनों में यह सिलसिला चरम पर पहुंच जाता है।

मिलावटखोरी की यह प्रक्रिया लोगों के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव छोड़ेगी, इससे धंधेबाजों को भला क्या लेना-देना? उनका लक्ष्य तो मात्र पैसा बटोरना ही है, कोई जिए या मरे उनकी बला से! सम्पूर्ण आहार के रूप में लिया जाने वाला दूध शरीर के लिए अमृत समान है जोकि सभी आवश्यक तत्वों की पूर्ति करने में समर्थ माना गया है किंतु यदि दूध के नाम पर जहरीले तत्व शरीर में घुल जाएं तो इसका परिणाम भी तो सर्वथा विपरीत ही होगा न? मिलावट का यह गोरख धंधा शरीर पर अनेक दुष्प्रभाव छोड़ देता है। धवलता में जहरीले तत्वों की कलुषता घोलती मिलावट न केवल सामूहिक रूप में समाज के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करके अनेकानेक व्याधियों को न्यौता देने का सबब बन रही है बल्कि मानवीय मूल्यों पर घात करते हुए सामाजिक व नैतिक माहौल भी अस्वस्थ बना रही है।

मिलावट का धंधा करने वाले दगाबाज लोगों पर नकेल कसना अत्यावश्यक है। जनता की सेहत से खिलवाड़ करना कोई मामूली मुद्दा नहीं, इसे संजीदगी से लेना चाहिए। आवश्यक है कि विभिन्न माध्यमों से मिलावट जांचने संबंधी विधियों को लेकर पर्याप्त जन-जागरूकता फैलाई जाए। प्रशासनिक स्तर पर इस संदर्भ में युद्धस्तरीय जांच-पड़ताल होने के साथ दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जानी चाहिए अन्यथा जैसे कि विश्व संगठन की रिपोर्ट ने आशंका जताई है, मिलावट का यह सिलसिला 2025 में 87 प्रतिशत भारतीयों के स्वास्थ्य को घातक बीमारियों का शिकार बना सकता है।

दीपिका अरोड़ा

सरकारों को गिरा सकती है एक उंगली

अचानक मेरी विनम्र तर्जनी उंगली गर्व करने लगी है। इतने सालों में, यह एक आज्ञाकारी छोटा सा जीव रहा है। दिशा बताता, लिफ्ट के बटन दबाता, चाय में चीनी मिलाता और कभी-कभी मेरे कुत्ते को हिलाता जब वह मेरी चप्पल चबाता है। क्योंकि जब चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो इस उंगली ने एक नया रवैया अपना लिया है। जैसे ही मैंने सुबह का कप उठाया, उसने कहा, ''अब मैं सबसे महत्वपूर्ण हूं! मेरा एक छोटा सा दबाव पूरे देश को बदल सकता है!'' मैंने तर्क करने की कोशिश की। मैंने कहा, ''तुम बढ़ा-चढ़ाकर कह रही हो।'' तुम 10 उंगलियों में से बस एक उंगली हो।'' उंगली ने आत्मसंतुष्ट होकर कहा, ''हां,लेकिन मैं चुनी हुई हूं। चुनाव आयोग ने खुद यह आदेश दिया है। मतदान के दिन, वे मुझे एक शाही बैंगनी निशान से सम्मानित करेंगे । यह इस बात का प्रमाण है कि लोकतंत्र मेरे आगे नतमस्तक है। आपके हाथ की कोई और उंगली यह दावा नहीं कर सकती।'' सच है, है न? बाईं तर्जनी उंगली पर लगाई गई वह अमिट स्याही, इस साधारण उंगली को राष्ट्रीय नायक बना देती है। कुछ दिनों तक वह बैंगनी रंग के गर्व से सजी घूमती रहती है जबकि बाकी सभी उंगलियां खामोश ईर्ष्या से देखती रहती हैं। और वह स्याही कितनी चमकती है! कोई भी साबुन,सैनिटाइजर या रगड़ कर उसे मिटा नहीं सकता। अगर आपने गलत व्यक्ति को वोट दिया है तो अपराधबोध भी उसे नहीं धो सकता। यह एक ऐसा टैटू है जो न सिर्फ यह दर्शाता है कि आप कहां रहे हैं बल्कि यह भी कि आपने क्या किया है,आपकी पसंद क्या है। यह अपनी आवाज और अपनी जिम्मेदारी का प्रतीक है। लेकिन मुझे मानना होगा कि मेरी उंगली का गर्व गलत नहीं है। क्योंकि एक क्षण के लिए, यह लोकतंत्र ही है जो सीधा खड़ा है, आरोप लगाने के लिए नहीं बल्कि पुष्टि करने के लिए इशारा कर रहा है कि मैंने वोट दिया है। और फिर भी, हम कितनी जल्दी उस गर्व को मिटने देते हैं! एक बार स्याही गायब हो जाए तो उसकी असली कीमत भी मिट जाती है। हम भ्रष्टाचार, बलात्कार, लिंचिंग और टूटे वादों पर उंगली उठाना बंद कर देते हैं। इसकी बजाय हम सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने और राजनीतिक चुटकुले फॉरवर्ड करने में इसका इस्तेमाल करते हैं।'' क्या तुम्हें पता है कि मुझे सबसे ज्यादा क्या दुख देता है?'' आज मेरी उंगली ने रूठ कर पूछा। ''5 साल में बस एक बार ही मेरी अहमियत होती है! तुम मुझे सैल्फी के लिए दिखाते हो, फिर भूल जाते हो कि मैं हूं भी!''अब क्या?'' मैंने आह भरी। मैं इससे इंकार नहीं कर सकता। क्योंकि यह सच है। मेरी यह छोटी सी उंगली, अगर सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो सरकारों को गिरा सकती है ईमानदारों को ऊपर उठा सकती है और सत्ता में बैठे लोगों को याद दिला सकती है कि उन्हें किसने वहां बिठाया है। तो हां, मेरी विनम्र तर्जनी उंगली को गर्व करने का पूरा हक है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने कपला ऑफसेट प्रिंटर्स, ए-9, सराय पीपलथला एक्स, दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2011/00882)

भटनी पुलिस ने 24 घण्टे में हत्या का किया खुलासा, आरोपी गिरफ्तार

खैराट पुल के पास से दबोचा गया धर्मखोर दूबे निवासी अभियुक्त

भटनी देवरिया।

पुलिस अधीक्षक देवरिया संजीव सुमन के निर्देश पर चलाए जा रहे अपराध नियंत्रण अभियान के तहत भटनी पुलिस ने एक हत्या की घटना का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी सुनील कुमार सिंह के कुशल निर्देशन और क्षेत्राधिकारी भाटपार रनी अंशुमान श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण में यह कार्रवाई की गई। थाना भटनी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर रोहित कुशवाहा पुत्र विजय बहादुर कुशवाहा निवासी धर्मखोर दूबे थाना खामपार जनपद देवरिया को शुक्रवार को खैराट पुल के पास से गिरफ्तार किया। अभियुक्त के विरुद्ध मु.अ.सं.-217/2025 धारा 103(1) बीएनएस के तहत अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। गौरतलब है कि वादी हदीश पुत्र स्व. बुद्धू मियां निवासी ग्राम धर्मखोर दूबे थाना खामपार ने 16 अक्टूबर को अपनी पुत्री का शव संदिग्ध परिस्थितियों में खेत में मिलने की सूचना भटनी थाना पुलिस को दी थी। पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर जांच प्रारंभ की और 24 घंटे के भीतर घटना का सफल अनावरण करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्त रोहित कुशवाहा पुत्र विजय बहादुर कुशवाहा निवासी धर्मखोर दूबे, थाना खामपार, जनपद देवरिया। गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम प्रभारी निरीक्षक जितेन्द्र सिंह, उपनिरीक्षक इन्द्रेश यादव,कांस्टेबल रंजीत मद्देशिया, शिवप्रकाश पाण्डेय, गौरव यादव, अमृत कुमार, संजय कुमार,महिला कांस्टेबल रुपम चौधरी,नन्दिनी थाना भटनी, जनपद देवरिया रहे।

बहादुर यादव महाविद्यालय भटनी में दीपावली पर रंगोली व दीप सजाओ प्रतियोगिता आयोजित

भटनी देवरिया।

नगर पंचायत भटनी स्थित बहादुर यादव महाविद्यालय (कॉलेज कोड-910) में शुक्रवार को राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस)के अंतर्गत दीपावली पर्व के अवसर पर रंगोली एवं दीप बनाओ&दीप सजाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं, स्वयंसेवकों एवं स्वयंसेविकाओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।कार्यक्रम का शुभारंभ माँ सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्ज्वलन एवं माल्यार्पण कर किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि महाविद्यालय की निदेशिका ममता यादव ने कहा कि दीपावली पर्व प्रकाश, सौहार्द और खुशी का प्रतीक है। रंगोली बनाने की परंपरा भगवान श्रीराम के अयोध्या आगमन की खुशी में प्रारंभ हुई थी। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ राकेश कुमार तिवारी ने कहा कि दीपावली का पर्व पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। दीप जलाने से जीवन में सकारात्मकता और नई ऊर्जा आती है। उप प्राचार्य डॉ आर.एम. यादव ने कहा कि रंगोली से

वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और घर में सुख-शांति बनी रहती है। दीपावली का पर्व प्रकाश और प्रेम का संदेश देता है।

एनएसएस के तहत विद्यार्थियों ने दिखाई रचनात्मकता, दीपों की रौशनी से महाविद्यालय परिसर जगमगाया

इस अवसर पर कार्यक्रम अधिकारी डॉ अनूप कुमार, डॉ. कंचन मिश्रा, तारा ठाकुर, प्रतिभा पटेल, वीरेन्द्र प्रताप विश्वकर्मा, राजीव शर्मा, दिवाकर यादव, अनीता विश्वकर्मा, शिवशंकर मौर्य, दुर्गेश यादव, राहुल यादव, मार्कंडेय यादव एवं संदीप यादव सहित महाविद्यालय के शिक्षक-शिक्षिका और कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

जनपद स्तरीय रबी उत्पादकता गोष्ठी का हुआ आयोजन

कुशीनगर। जनपद में किसानों के साथ-साथ आम जनमानस को मिलेट्स (श्री अन्न) के प्रयोग व प्रभाव से परिचित कराने, उनसे होने वाले स्वास्थ्य सम्बन्धी लाभ आदि विषय पर मिलेट्स (श्री अन्न) रेसीपी एवं उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम एवं जनपद स्तरीय रबी उत्पादकता गोष्ठी का आयोजन शुक्रवार को प्रातः 11.00 बजे से जिला पंचायत रिसोर्स सेन्टर, रविन्द्रनगर में आयोजित किया गया। राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त राजेश्वर सिंह ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। कार्यक्रम में जनपद स्तरीय विभिन्न अधिकारियों,कृषि विभाग के कर्मचारी एवं कृषक बन्धुओ द्वारा मिलेट्स (श्री अन्न) के बाजरा,रागी,सांवा, रामदाना आदि से बने व्यजंन का सेवन किया गया। इस अवसर श्री अन्न के उपयोगिता एवं उससे होने वाले लाभ के बारे में जानकारी दी गयी। इस जागरूकता कार्यक्रम में राजकीय संविलय विद्यालय रविन्द्रनगर के लगभग 70 छात्रायें, प्राविधान कृषक उत्पादक संगठन, प्रगति स्वयं सहायता समूह, कृषि सखियों एवं राजकीय विद्यालयों के छात्र एवं छात्राओं द्वारा प्रतिभाग किया। मिलेट्स उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम के अन्तर्गत राजकीय विद्यालय के छात्राओं के उत्साहवर्धन हेतु पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें छात्राओं को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया इसी के साथ अन्य सभी प्रतिभागी को सात्वना पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र मुख्य अतिथि द्वारा प्रदान किया गया। मुख्य अतिथि द्वारा जनपद के कृषकों में राई/सरसों के मिनीकिट बीज का वितरण किया एवं अपने उद्बोधन में मिलेट्स से होने वाले स्वास्थ्य लाभ तथा सरकार के विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी गयी। इस अवसर पर उप कृषि निदेशक अतीन्द्र सिंह द्वारा मिलेट्स से होने वाले स्वास्थ्य लाभ के बारे में जानकारी के साथ-साथ कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं मे मिलने वाले अनुदान पर विस्तृत जानकारी प्रदान की ।

धनतेरस और दीपावली पर शहर में यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव

देवरिया।

धनतेरस और आगामी दीपावली पर्व के मद्देनज़र शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने व्यापक तैयारी कर ली है। शहर में बढ़ने वाली भीड़ और बाजारों में खरीदारी के दौरान जाम की समस्या से निपटने के लिए आज से 21 अक्टूबर तक विशेष यातायात डायवर्जन प्लान लागू किया गया है।

यह व्यवस्था प्रतिदिन सुबह 8:30 बजे से लेकर रात्रि 2:00 बजे तक प्रभावी रहेगी। पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के निर्देश पर तैयार इस योजना के तहत शहर में भारी वाहनों (ट्रक, ट्रैक्टर-ट्रॉली, बड़ी बसें, मिक्सर वाहन, गैस सिलेंडर व पेट्रोल-डीजल टैंकर) का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इन वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से शहर की परिधि से होकर गंतव्य तक भेजा जाएगा ताकि बाजार क्षेत्र में भीड़भाड़ की स्थिति न बने और नागरिक निर्बाध रूप से पर्व की खरीदारी कर सकें। जानकारी के अनुसार, सलेमपुर की दिशा से आने वाले भारी वाहन सोनूघाट चौराहा से पिपरपाती नहर मार्ग की ओर डायवर्ट किए जाएंगे। वहीं रूद्रपुर मोड़ तिराहा से आने वाले वाहन कतरारी तिराहा होते हुए अमेठी मार्ग से अपने गंतव्य की ओर भेजे जाएंगे। इसी प्रकार गोरखपुर मार्ग से आने वाले वाहन पूरवों तिराहा से पांडेयचक मार्ग पर डायवर्ट किए जाएंगे। कसया रोड से आने वाले वाहनों को धनौती तिराहा से आगे सोमनाथ मंदिर की दिशा में मोड़ दिया जाएगा, जबकि बरियारपुर से आने वाले वाहन पिपरपाती चौराहा होते हुए वैकल्पिक मार्ग से अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। पुलिस ने बताया कि केवल सब्ज़ी और फल मंडी के वाहनों को ही मण्डी तक प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। छोटे वाहनों के लिए भी कड़े प्रावधान किए गए हैं। कोतवाली तिराहा से कोई भी ई-रिक्शा या टैम्पू मोतीलाल रोड की ओर नहीं जा सकेगा, इसी प्रकार मोतीलाल रोड तिराहा से कोतवाली मार्ग की दिशा में भी ई-रिक्शा व टैम्पू का प्रवेश वर्जित रहेगा। इसके अलावा कोऑपरेटिव से हनुमान मंदिर की ओर और हनुमान मंदिर से कोऑपरेटिव की दिशा में भी ई-रिक्शा और टैम्पू के आवागमन पर रोक रहेगी। पुलिस प्रशासन ने अपील की है कि नागरिक यातायात व्यवस्था में सहयोग करें और निर्धारित मार्गों का पालन करें। यातायात व्यवस्था के सुचारु संचालन के लिए शहर के प्रमुख स्थानों पर पुलिस बल की विशेष तैनाती की जाएगी। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि त्योहारों के दौरान आमजन की सुविधा और सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। जाम-मुक्त, सुरक्षित और शांतिपूर्ण दीपावली मनाने के लिए पुलिस हर संभव व्यवस्था कर रही है।

चार दिन तक लागू रहेगा डायवर्जन प्लान

विधायक के प्रस्ताव पर विशेष मरम्मत के लिए 3.91 किमी लंबी नौ नई सड़कें स्वीकृत

- अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में 8.9 किमी लंबी 11 जर्जर सड़कों को मिल चुकी है स्वीकृति
- अब 12.81 किमी लंबी कुल 20 सड़कों का होगा कायाकल्प, आवागमन होगा आसान

तमकुही राज,कुशीनगर ।

विधायक सुरेंद्र कुमार कुशवाहा के प्रस्ताव पर शासन से गत 14 अक्टूबर को फाजिलनगर विधान सभा क्षेत्र की अति जर्जर हो चुकी नौ सड़कों के विशेष मरम्मत की स्वीकृति मिली है।

ये सड़कें फाजिलनगर विधान सभा के लिए अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में 8.9 किमी लंबाई में स्वीकृत 11 जर्जर सड़कों से अलग हैं। नौ सड़कें जो लोक निर्माण विभाग की ओडीआर (अदर डिस्ट्रिक रोड) में स्वीकृत हैं, उनमें बरवा राजापाकड़-दुमही-मंझरिया मार्ग (1000 मी.), गुरवलियाडुंदही मार्ग किमी 3 से विजयपुर उत्तर पट्टी खटिक टोला सम्पर्क मार्ग (200 मी.), पृथ्वीपुर महतो टोला सम्पर्क मार्ग (300 मी.), बीएमसीटी से बड़हरा खुर्द सम्पर्क मार्ग (500 मी.), लबनिया हरिजन बस्ती सम्पर्क मार्ग (500 मी.), चैनपुर नोनिया टोली मार्ग से बड़हरा टोला सम्पर्क मार्ग (400 मी.), तुर्कपट्टीडुत्तेजवलिया सम्पर्क मार्ग (340 मी.), जोकवा बन्जरिया से विशुनपुरा सम्पर्क मार्ग (200 मी.) व जोकवा बन्जरिया किमी 3 से माधोपुर सम्पर्क मार्ग (470 मी.) शामिल हैं। इन नौ सड़कों की कुल लंबाई 3.91 किमी है। जबकि अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में 8.9 किमी लंबी 11 सड़कों को मिलाकर अब वित्तीय वर्ष 2025-26 में विधानसभा क्षेत्र के लिए कुल 12.81 किमी लंबी 20 सड़कों के विशेष मरम्मत की स्वीकृति मिल चुकी है।

पिछड़ा मोर्चा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष डा. डीएन कुशवाहा, डा. कन्हैया शर्मा, अमलेश तिवारी, श्रीनिवास राय, लोकनाथ सिंह, डा. काशी वर्मा आदि कार्यकर्ताओं ने हर्ष जताया है। विधायक सुरेंद्र कुमार कुशवाहा ने कहा कि शासन स्तर से स्वीकृत यह योजना क्षेत्र के ग्रामीण संपर्क को मजबूत करेगी व विकास को गति देगी। कहा कि कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग शीघ्र ही उक्त कार्य योजनाओं के लिए टेंडर जारी कर कार्य शुरु कराएगा।

पूर्व मंत्री स्व. रवीन्द्र किशोर शाही की 43वीं पुण्य स्मृति पर क्षेत्रीय किसान मेला का भव्य शुभारंभ

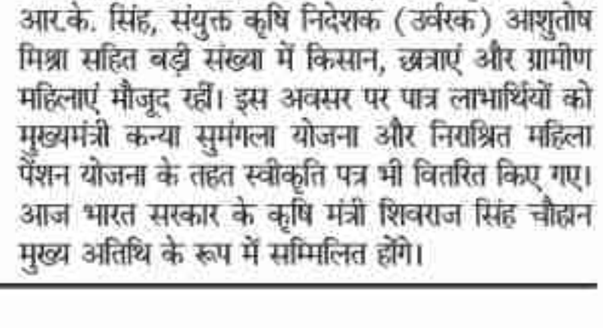

कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही बोले – सरकार महिलाओं, किसानों और युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध

देवरिया । पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जनसंघ एवं उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री स्वर्गीय रवीन्द्र किशोर शाही की 43वीं पुण्य स्मृति पर शुक्रवार को देवरिया के आचार्य नरेन्द्र देव इंटर कॉलेज, पथरदेवा में दो दिवसीय क्षेत्रीय किसान मेला, स्वास्थ्य शिविर और मिशन शक्ति 5.0 जन-जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने दीप प्रज्वलन एवं सरस्वती वंदना के साथ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों, महिलाओं और युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए सतत प्रयासरत है। महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता के लिए संचालित योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं का सशक्तिकरण ही समाज के विकास की असली ताकत है। मेले में कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य, गन्ना, रेशम, सहकारिता, सिंचाई, विद्युत, स्वास्थ्य, बैंकिंग, एनजीओ और एफपीओ सहित विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाए गए, जिनके माध्यम से किसानों को सरकारी योजनाओं और नवीनतम कृषि तकनीकों की जानकारी दी गई। इस दौरान कृषि वैज्ञानिक डॉ. आर.के. मलिक (आईआरआरआई वाराणसी), डॉ. एस.के. नायक (इफ्को), डॉ. संजीव तेतरिया (इफ्को लखनऊ), डॉ. आर.आर. सिंह (कुमारगंज फैजाबाद) और डॉ. मान्धाता सिंह (केवीके) ने किसानों को उर्वरक प्रबंधन, बीज गुणवत्ता, कीट नियंत्रण, आधुनिक कृषि विधियों और उत्पादन बढ़ाने के व्यावहारिक उपायों पर मार्गदर्शन दिया। साथ ही मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अंतर्गत महिलाओं और बालिकाओं के सम्मान, सुरक्षा और स्वावलंबन से जुड़ी योजनाओं पर विशेष सत्र आयोजित हुआ। महिला कल्याण विभाग की टीम – नीतू भारती (केंद्र प्रशासक), मीनू जायसवाल (मनोवैज्ञानिक), मंशा सिंह (जेंडर स्पेशलिस्ट) तथा अरविंद यादव ने महिला हेल्पलाइन 181, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, वन स्टॉप सेंटर, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना और निराश्रित महिला पेंशन योजना सहित कई कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी देवरिया, संयुक्त कृषि निदेशक गोरखपुर मंडल, उप कृषि निदेशक, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, जिला गन्ना अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी, अपर कृषि निदेशक आर.के. सिंह, संयुक्त कृषि निदेशक (उर्वरक) आशुतोष मिश्रा सहित बड़ी संख्या में किसान, छात्राएं और ग्रामीण महिलाएं मौजूद रहीं। इस अवसर पर पात्र लाभार्थियों को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना और निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत स्वीकृति पत्र भी वितरित किए गए। आज भारत सरकार के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होंगे।

धूल-धुआं और पराली से निपटने के लिए दिल्ली सरकार का विंटर एक्शन प्लान तैयार, आगजनी पर निगरानी

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने राजधानी को प्रदूषण के कुहासे से बचाने के लिए 'विंटर एक्शन प्लान 2025-26' लागू कर दिया है. अक्टूबर से फरवरी तक चलने वाले इस अभियान का लक्ष्य है साफ हवा, सर्दी में राहत और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी. सात थीम और 25 एक्शन पॉइंट्स पर आधारित यह प्लान 30 से अधिक एजेंसियों की संयुक्त जिम्मेदारी बनेगा. पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में तय हुआ कि इस सर्दी प्रदूषण नियंत्रण के नियमों में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी. उन्होंने स्पष्ट किया, धूल नियंत्रण हो, निर्माण स्थल के नियम हों या उद्योगों का पीएनजी पर संचालन, हर विभाग को गति और फोकस के साथ काम करना होगा. ग्रीन वॉर रूम से सभी कार्रवाइयों की रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी. मंत्री ने कहा कि पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, एनडीएमसी, डीएसआईआईडीसी, डीपीसीसी और दिल्ली पुलिस को रोजाना समन्वय बनाकर रिपोर्ट देनी होगी. राजधानी की सड़कों पर सफाई और धूल नियंत्रण के लिए 86 मैकेनिकल रोड स्वीपर, 300 स्प्रिंकलर और 362 एंटी-स्मॉग गन पहले से तैनात हैं. इसके साथ 70 और नए उपकरण जोड़े जा रहे हैं. सभी प्रमुख सड़कों की वैक्यूम क्लीनिंग जीपीएस से ट्रैक होगी. 500 वर्गमीटर से बड़े हर निर्माण प्रोजेक्ट का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, जबकि 3,000 वर्गमीटर या जी+5 मंजिल से अधिक की इमारतों में एंटी-स्मॉग गन लगाना जरूरी होगा. साथ ही, 698 किलोमीटर सड़क किनारे पेविंग और 85 किलोमीटर मिड-वर्ज ग्रीनिंग का लक्ष्य तय किया गया है. 578 प्रवर्तन टीमें सड़कों पर लगातार निगरानी कर रही हैं ताकि धुएं, पीयूसी उल्लंघन और इंजन चालू रखने जैसी गतिविधियों पर रोक लग सके. 953 पीयूसी केंद्र अब ट्रांसपोर्ट विभाग के लाइव डैशबोर्ड से जुड़े हैं. गंभीर प्रदूषण स्तर पर पार्किंग शुल्क दोगुना होगा ताकि निजी वाहनों का उपयोग घटाया जा सके. डीएसआरसी की ई-ऑटो फ्लीट 2,299 तक बढ़ाई जाएगी और नए वाहन पंजीकरणों में ईवी का हिस्सा 12फीसदी से अधिक रखने का लक्ष्य है. दिल्ली के सभी उद्योग अब पीएनजी पर चल रहे हैं. डीएसआईआईडीसी और डीपीसीसी की संयुक्त टीमें अनधिकृत ईंधन के प्रयोग पर सख्त कार्रवाई करेंगी. केवल ड्यूअल-फ्यूल या उत्सर्जन-अनुपालक डीजी सेट को ही अनुमति होगी, जबकि आवश्यक सेवाओं को सीमित छूट दी जाएगी. पुनर्विकास क्षेत्रों में उद्योगों के लिए कंक्रीट मैनेजमेंट सिस्टम दोबारा लागू किया गया है. 443 टीमें 24x7 गश्त कर रही हैं ताकि कचरा या बायोमास जलाने की घटनाओं को रोका जा सके. 2025 में किसी भी लैंडफिल में आग नहीं लगी है, क्योंकि सभी स्थलों पर स्थायी वॉच टावर और हाइड्रेंट लगाए गए हैं. अब तक 136.27 लाख टन पुराने कचरे की बायोमाइनिंग पूरी हो चुकी है. ओखला, भलस्वा और गाजीपुर लैंडफिल साइट्स की सफाई क्रमशः जुलाई 2026, दिसंबर 2026 और दिसंबर 2027 तक पूरी करने की समयसीमा तय की गई है. वेस्ट-टू-एनर्जी क्षमता को 7,834 टीपीडी से बढ़ाकर 14,000 टीपीडी तक करने की तैयारी है. दिल्ली के खेतों में 100फीसदी PUSA Decomposer का छिड़काव लगभग पूरा कर लिया गया है ताकि पराली जलाने की जरूरत न पड़े. विशेष मोबाइल पेट्रोल टीमें रियल टाइम रिपोर्टिंग कर रही हैं और 1,400 से अधिक आरडब्ल्यूए को हीटर दिए गए हैं ताकि गार्ड्स आग जलाने से बचें. सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के अनुसार, दिल्ली में सिर्फ NEERI-प्रमाणित ग्रीन पटाखे ही बेचे और चलाए जा सकेंगे, 18 और 19 अक्तूबर को, सुबह 6-7 बजे और रात 8-10 बजे के बीच, केवल लाइसेंस प्राप्त स्थलों पर. केवल क्यूआर कोड वाले पटाखे ही वैध होंगे.

सीएम नीतीश कुमार से मिले अमित शाह

- गृह मंत्री बोले- जनता लालू यादव का जंगलराज वापस नहीं लाएगी
- एनडीए में सीएम फेस पर अब भी सवाल, गृह अमित शाह बोले- चुनाव के बाद गठबंधन मिलकर तय करेगा

पटना।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की है। शुक्रवार सुबह 10:57 बजे सीएम नीतीश से मुलाकात करने पटना के अणे मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। करीब 18 मिनट बाद दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। इसके बाद गृह मंत्री एयरपोर्ट पहुंचे। यहां से वह छपरा के तरैया के लिए निकल गए। वहां पर वह जनसभा को संबोधित करेंगे। इधर, पटना में उन्होंने एनडीए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बिहार में इस बार एनडीए को ऐतिहासिक जीत मिलेगी।

उन्होंने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद पर हमला बोलते हुए कहा कि चाहे केंद्र में हो या राज्य में, लालू यादव जहां भी सत्ता में रहे, वहां जमकर भ्रष्टाचार किया। 21वीं सदी में बिहार की जनता कभी भी लालू यादव का जंगलराज वापस नहीं लाएगी। लालू यादव को रोड, पुल, पानी, आवास पर चर्चा करना शोभा नहीं देता, उन्हें केवल अपने जंगलराज, अपहरण, फिरौती, वसूली पर चर्चा करनी चाहिए। सीएम नीतीश कुमार और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर बताया जा रहा है कि एनडीए में सीट बंटवारे के बाद सीएम नीतीश कुमार अपने खाते की कुछ सीटें केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी को मिलने से नाराज हो गए थे। इसके बाद उन्होंने सीएम हाउस में भाजपा और जदयू के वरिष्ठ नेताओं की अलग-अलग बैठक भी बुलाई थी। इस बैठक के बाद ही भाजपा और जदयू ने अपने अपने उम्मीदवार उतारे। उस वक्त भी यह बात सामने आई थी कि गृह मंत्री अमित शाह पटना आते ही मुलाकात करेंगे। आज दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हो गई। बैठक के दौरान गृह मंत्री ने बिहार चुनाव की तैयारी, प्रचार प्रसार समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत की। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि आगामी चुनाव को लेकर यह मुलाकात हुई। एनडीए में सबकुछ ठीक है। सबलोग एकजुट हैं। हमलोगों को जनता ने आशीर्वाद दिया है।

छत्तीसगढ़ सरकार के हाथ लगी बड़ी सफलता, 208 नक्सलियों ने बीजीएल लॉन्चर और एके-47 समेत 153 हथियार किए सरेंडर

नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ चल रहे अभियान को आज एक बड़ी सफलता मिली है। 17 अक्टूबर 2025 को दंडकारण्य क्षेत्र के 208 नक्सलियों ने अपने हथियार डालकर आत्मसमर्पण कर दिया है। इन नक्सलियों ने कुल 153 घातक हथियार सुरक्षा बलों के सामने सौंपे हैं। छत्तीसगढ़ में इस आत्मसमर्पण को अच्छा संकेत माना जा रहा है। इसके साथ ही अबूझमाड़ क्षेत्र अब लगभग पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो गया है, जिससे उत्तर बस्तर से लाल आतंक खत्म होने की उम्मीद बढ़ गई है। अब सिर्फ दक्षिण बस्तर के कुछ हिस्सों में ही समस्या बाकी बची है। यह आत्मसमर्पण दंडकारण्य के इतिहास में सबसे बड़ा माना जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार पिछले दो दिनों में कुल

258 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, जिनमें छत्तीसगढ़ से 197 और महाराष्ट्र से 61 नक्सली शामिल हैं। आत्मसमर्पण करने वालों में नक्सली संगठन के कई बड़े कमांडर भी शामिल हैं, जो अब मुख्यधारा में लौटना चाहते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को खत्म करने का लक्ष्य दोहराया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साई ने भी इस पहल को शांति और विकास का नया दौर बताते हुए कहा कि नक्सलवाद हर मोर्चे पर हार रहा है।

सरेंडर किए गए हथियारों का जखीरा

आत्मसमर्पण के दौरान नक्सलियों द्वारा जमा करवाए गए 153 हथियारों में कई आधुनिक और घातक हथियार शामिल हैं। सुरक्षा बलों को बड़ी राहत देते हुए ये हथियार अब सरकारी कब्जे में हैं।

नक्सलवाद का अंतिम गढ़ हुआ शांत

अबूझमाड़ जो छत्तीसगढ़ का घना जंगल क्षेत्र है और सालों से नक्सलियों का आखिरी बड़ा गढ़ बना हुआ था, आज के सामूहिक आत्मसमर्पण के बाद लगभग शांत हो चुका है। अब उत्तर बस्तर भी सुरक्षित है। इस शांति के बाद इन क्षेत्रों में विकास कार्यों (सड़कें, स्कूल, अस्पताल) में तेजी आने की उम्मीद है, जिससे लोग बिना डर के जीवन जी सकेंगे। सरकार की सख्त कार्रवाई और प्रभावी सरेंडर नीति से ही यह बदलाव संभव हो पाया है।

मोदी ने पंजाब के मुख्यमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी

नई दिल्ली।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को शुक्रवार को जन्मदिन की बधाई दी और उनके दीर्घायु एवं स्वस्थ जीवन की कामना की। मोदी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर लिखा, ''पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर उन्हें दीर्घायु और स्वस्थ जीवन प्रदान करें।'' हास्य कलाकार एवं नेता मान ने 16 मार्च, 2022 को पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी।

गुजरात में नई कैबिनेट का शपथग्रहण

हर्ष संघवी उपमुख्यमंत्री; सीएम समेत 8 मंत्री पटेल समाज से- 19 नए चेहरे

गांधीनगर। गुजरात में नए मंत्रिपरिषद का आज शपथ ग्रहण समारोह हुआ। हर्ष संघवी को राज्य का नया डिप्टी सीएम बनाया गया है। हर्ष संघवी तीन बार के विधायक हैं और फिलहाल मजुरा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने 25 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई, जिसके बाद सीएम भूपेंद्र पटेल को मिलाकर मंत्रीपरिषद में 26 मंत्री हो गए हैं। पिछले साल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए विधायक अर्जुन मोढवाडिया को भी मंत्री बनाया गया है। विसनगर विधायक ऋषिकेश पटेल, प्रफुल पनशेरिया, कुंवरजी बावलिया को फिर से मंत्रीपरिषद में शामिल किया गया है।

इन विधायकों को मिली मंत्रिपरिषद में जगह

कनुभाई देसाई, पुरुषोत्तम सोलंकी, नरेश पटेल, अहमदाबाद की पूर्व डिप्टी मेयर दर्शना वाघेला, गुजरात भाजपा एससी मोर्चा के पूर्व प्रमुख प्रद्युमन वाजा, मोरबी विधायक कांतिलाल अमृतिया और वडोदरा विधायक मनीषा वकील को भी मंत्रिपरिषद में जगह मिली है। गुरुवार को गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल को छोड़कर मंत्रिपरिषद के अन्य सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था। गुजरात भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और भावनगर से विधायक जीतू वाघाणी, अमरेली से विधायक और भाजपा के डिप्टी चीफ व्हिप कौशिक वेकारिया, स्वरूपजी ठाकोर, टीकाराम छंगा, जयराम गामित, जामनगर उत्तर विधायक रिवाबा जडेजा, पीसी बरंडा, दाहोद विधायक रमेश कटारा, अंकलेश्वर विधायक ईश्वरसिंह पटेल, दीसा विधायक प्रवीण माली, बारसोड विधायक रमनभाई सोलंकी, पेटलाद विधायक कमलेश पटेल, महुधा विधायक संजय सिंह महिदा को भी मंत्रिपरिषद में जगह मिली है।

2027 विधानसभा चुनाव के लिहाज से अहम है ये फेरबदल

गुजरात सरकार के मंत्रिपरिषद में यह फेरबदल भाजपा के मिशन 2027 के लिहाज से अहम माना जा रहा है। पार्टी आगामी निकाय चुनाव में नए सामाजिक समीकरणों को परखने की तैयारी कर रही है। पार्टी का मानना है, युवा विधायकों को मंत्रिपरिषद में शामिल करने से युवा नेताओं का हौसला और सरकार में ओबीसी-पाटीदार प्रतिनिधित्व बढ़ा है। आगामी चुनाव में भाजपा को इसका फायदा मिल सकता है। विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा गुजरात में सुनिश्चित करना चाहती है कि पाटीदार समुदाय के साथ ओबीसी और शहरी वर्ग का संतुलन बना रहे। विश्लेषक मानते हैं कि चेहरे बदलकर भाजपा राज्य में लंबे समय से चल रही सरकार के प्रति होने वाली एंटी इनकंबेंसी को खत्म कर रही है।

सीएम योगी ने खातों में भेजी 297 करोड़ की छात्रवृत्ति, बोले- पहले चयन प्रक्रिया में भेदभाव होता था

लखनऊ।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकभवन में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा आयोजित छात्रवृत्ति वितरण समारोह में डीबीटी से करीब पांच लाख युवाओं के खातों में छात्रवृत्ति ट्रांसफर की। सरकार ने पहली बार वित्तीय वर्ष 2025-26 से सितंबर में ही छात्रवृत्ति वितरण की शुरुआत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में सभी छात्र-छात्राओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि पहले छात्रवृत्ति के लिए छात्रों के चयन की प्रक्रिया में भेदभाव होता था। वर्ष 2016-17 में तो अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति ही हड़प ली गई थी पर अब ऐसा नहीं होता है। अब प्रदेश के 62 लाख छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति मिल रही है। जब हम सत्ता में आए तो तय किया कि छात्रों को वर्ष के अंत में नहीं बल्कि

दो बार में छात्रवृत्ति दी जाए। जो कि अब संभव हो रहा है। यह बदली हुई व्यवस्था का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि अब डीबीटी के माध्यम से विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जा रही है जिससे कि छात्र-छात्राओं को कहीं भी भटकना न पड़े। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यार्थियों से स्कूल जाने की अपील की और कहा कि पढ़ाई जरूर करें। इससे पूरा समाज बदलेगा। पहले चरण में लगभग 62.13 करोड़ रुपये कक्षा 9 से 12 तक के 2.5 लाख ओबीसी छात्रों को दिए जा चुके हैं।

दूसरे चरण में शुक्रवार को 126.68 करोड़ रुपये 4.83 लाख से अधिक छात्रों को दिए गए। इस मौके पर यूपी सरकार के मंत्री असीम अरुण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशानुसार यूपी सरकार अब ई गवर्नेंस से ईजी गवर्नेंस की तरफ बढ़ रही है।

पूरे देश में अनुसूचित जाति पर अत्याचार हो रहा, रायबरेली में राहुल गांधी ने कहा- मैं लड़ूंगा लड़ाई

उत्तर प्रदेश दलित लिंचिंग पर गरमाई सियासत, राहुल गांधी का आरोप- सरकार परिवार को धमका रही है

रायबरेली।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को अपने निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली में लिंच किए गए दलित व्यक्ति हरिओम वाल्मीकि के परिवार से मुलाकात की। परिवार से मिलने के बाद, कांग्रेस नेता ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा कि सरकार ने पीड़ित परिवार को उनसे मिलने से मना किया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी परिवार को हर संभव मदद देने की पूरी कोशिश करेगी, और कहा कि देश में जहां भी दलितों पर अत्याचार होगा, कांग्रेस वहां मौजूद रहेगी और हम हर संभव मदद करेंगे और न्याय के लिए लड़ेंगे। वाल्मीकि (40) की कथित तौर पर ग्रामीणों ने 2 अक्टूबर की रात लगभग 1 बजे एक रात्रि जागरण के दौरान चोर समझकर पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। यह अफवाह थी कि एक गिरोह चोरी के लिए घरों पर निगरानी रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए, गांधी ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश सरकार परिवार को धमका रही है और उन्हें उनसे न मिलने का निर्देश दिया है। कांग्रेस नेता ने कहा, परिवार ने कोई अपराध नहीं किया है। उनके खिलाफ अपराध हुआ है और ऐसा लगता है कि वे ही अपराधी हैं। उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। उन्हें धमकाया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा, परिवार ने मुझे बताया कि सरकारी अधिकारियों ने परिवार को धमकाया है और मुझसे न मिलने का निर्देश दिया है। उन्होंने परिवार के सामने आने वाली बाधाओं पर प्रकाश डाला, जिसमें सर्जरी का इंतजार कर रही बेटी की चिकित्सा देखभाल भी शामिल है। उन्होंने कहा कि सरकार ने उन्हें पूरी तरह से बंद कर दिया है। गांधी ने कहा, देश भर में दलितों पर अत्याचार, हत्याएं और बलात्कार हो रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए। उनका सम्मान किया जाना चाहिए। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें संरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए।

महागठबंधन में वीआईपी की डील फाइनल: मुकेश सहनी नहीं लड़ेंगे चुनाव, बंटवारे में 15 सीट के अलावा मिला यह ऑफर

पटना।

बिहार चुनाव के पहले चरण की विधानसभा सीटों पर नामांकन का आज आखिरी दिन है। अब तक महागठबंधन यह घोषणा नहीं की है की किस दल को कितनी सीटें दी गई है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस बात को लेकर पेंच फंसा हुआ था, उसका समाधान हो गया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के करीबी और विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी की डील अंततः फाइनल हो गई है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने उन्हें महागठबंधन में उचित सम्मान का भरोसा दिलाया। साथ ही उनके खाते में 15 सीटें दी है। इतना ही नहीं मुकेश सहनी को राज्यसभा और विकासशील इंसान पार्टी के दो लोगों को विधान परिषद भेजा जाएगा, यह बात भी तय हो गई। सहनी ने दरभंगा में स्पष्ट कहा कि इस बार मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। महागठबंधन को प्रत्याशियों को जिताने के लिए प्रचार-प्रसार करूंगा। महागठबंधन के मैं समर्पित हूं। सीट बंटवारे पर उन्होंने कहा कि सारी बात फाइनल हो चुकी है। एक से दो दिनों में सब बातें स्पष्ट हो जाएंगी।

इन सीटों पर सहनी उतारेंगे अपना उम्मीदवार

महागठबंधन में अपने मन मुताबिक डील मंजूर करने के बाद मुकेश सहनी दरभंगा पहुंचे। वहां उन्होंने अपने भाई को गौड़ाबौराम विधानसभा से चुनाव लड़ने का एलान किया। कहा कि चर्चा थी कि मुकेश सहनी इस सीट से खुद चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब उनके राज्यसभा जाने की बात हो रही है। इधर महागठबंधन में मुकेश सहनी के खाते में जो सीटें आई हैं, उनमें केसरिया, झंझारपुर, गोपालगंज, छातापुर, गौड़ाबौराम, भभुआ, रजौली, सहरसा, सकरा, अलीनगर, अमौर, हरनौत, नालंदा, बखनाहा, नौतन विधानसभा सीटें शामिल हैं।

मुकेश सहनी की प्रेशर पॉलिटिक्स से बनी बात

वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी शुरुआत में 50 सीट और डिप्टी सीएम का पद मांग रहे थे। कुछ दिन बाद 40 सीट और डिप्टी सीएम की मांग की। इसके बाद 20 सीट और डिप्टी सीएम के पद की मांग को लेकर अड़ गए। कुछ दिन पहले जब वह महागठबंधन के प्रमुख नेताओं से मिलने दिल्ली गए थे तो वहां पर उन्होंने कहा था कि महागठबंधन अभी बीमार हो गया है मैं इलाज करने आया हूं।

हरियाणा सरकार की सालगिरह पर सीएम सैनी का बुजुर्गों को तोहफा, बढ़ाई गई बुढ़ापा पेंशन

डेस्क। हरियाणा में नायब सैनी सरकार का आज यानी 17 अक्टूबर को एक साल पूरा हो रहा है। इस दौरान सीएम सैनी ने सरकार की सालगिरह पर बुजुर्गों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने बुढ़ापा पेंशन के 3000 से बढ़कर 3200 रुपये की वृद्धि की है। ये घोषणा 1 नवंबर से लागू होगी। जानकारी के अनुसार हरियाणा में नायब सैनी सरकार 1 साल पूरे हो गए हैं। इसको लेकर आज पंचकूला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुजुर्गों के लिए बड़ी की है। उन्होंने बुढ़ापा पेंशन 3000 से बढ़कर 3200 रुपये की। 1 नवंबर से नई बुढ़ापा पेंशन लागू होगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में सरकारी नौकरी व बुढ़ापा पेंशन दो सबसे बड़े मुद्दे हैं। इसके अलावा सैनी ने कहा कि कल यानी शनिवार को छुट्टी के दिन सभी तहसीलें खुली रहेंगी। साथ में कार्यक्रम में हरियाणा सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व में हरियाणा विकास की 'नॉनस्टॉप रफ्तार' के साथ आगे बढ़ रहा है। अपने पहले ही साल में हरियाणा सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले जनता से किए 217 में से 46 संकल्प पूरे कर लिए हैं। हरियाणा में अब वृद्धावस्था पेंशन 3200 प्रति माह हो गई है, जो कि 1 नवंबर 2025 से होगी। इस वृद्धि का लाभ राज्य के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा। इससे पहले, जनवरी 2024 में पेंशन को 2750 से बढ़ाकर 3000 किया गया था। अब 200 रुपए और बढ़ाए गए हैं।

कॉलेज वॉशरूम में सीनियर से दुष्कर्म करने के आरोप में छात्र गिरफ्तार, न्यायिक हिरासत में भेजा गया

बंगलूरू।

बंगलूरू के एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्रा के साथ उसके जूनियर छात्र ने कॉलेज परिसर के पुरुष वॉशरूम में कथित तौर पर दुष्कर्म किया। आरोपी छात्र बीई के पांचवें सेमेस्टर में पढ़ता है और वह पीड़िता को पहले से जानता था, जो उसी पाठ्यक्रम में सातवें सेमेस्टर में पढ़ती है। आरोपी को दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। शिकायत में पीड़िता ने बताया कि घटना 10 अक्तूबर को हुई। दोपहर के भोजन के अवकाश के दौरान आरोपी ने उसे कई बार फोन कर आर्किटेक्चर ब्लॉक की सातवीं मंजिल पर मिलने के लिए बुलाया। जब वह वहां पहुंची, तो आरोपी ने उसके साथ छेड़छाड़ की। जब वह वहां से लिफ्ट से जाने लगी, तो आरोपी उसके पीछे छठी मंजिल तक पहुंचा, जहां उसने उसे पुरुषों के वॉशरूम में घसीट लिया, दरवाजा बंद किया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने बताया कि इस दौरान आरोपी ने उसका मोबाइल फोन भी छीन लिया, जब उसकी एक सहेली ने उसे कॉल करने की कोशिश की। घटना के बाद छात्रा ने अपने दोस्तों को सब कुछ बताया। दोस्तों ने उसे माता-पिता को सूचित करने के लिए कहा। बाद में आरोपी ने उसे फोन करके पूछा कि क्या उसे %पिल% (आपातकालीन गर्भनिरोधक दवा) चाहिए, लेकिन छात्रा ने कॉल काट दी। शुरुआत में डर और झिझक के

आरोपी को दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

कारण छात्रा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में उसने अपने माता-पिता को सब बताया। इसके बाद 15 अक्तूबर को हनुमंतनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने बताया कि मामला भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64 (दुष्कर्म) के तहत दर्ज किया गया है।

नेता प्रतिपक्ष अशोक ने की सरकार की आलोचना

कर्नाटक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता आर अशोक ने आरोप लगाया कि राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध तेजी से बढ़े हैं और कानून-व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह बिगड़ गई। उन्होंने कहा कि बीते चारमहीनों में बालिकाओं पर यौन हमलों के 979 मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें से 114 से अधिक मामले केवल बंगलूरू में हैं। अशोक ने इस विषय में राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) की अध्यक्ष विजया किशोर रहाटकर को पत्र लिखकर दखल देने की मांग की है। उन्होंने एक्स पर लिखा, कर्नाटक में कानून-व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। सिर्फ चार महीनों में 979 यौन हमले। बंगलूरू में ही 114+ मामले। कांग्रेस सरकार की आपराधिक निष्क्रियता के कारण महिलाएं और बच्चे डर के माहौल में जी रहे हैं।